

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 19.05.2023

आयकर अपील 291/2023

प्रधान आयकर आयुक्त, दिल्ली -7

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री पुनीत राय, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता

*बनाम*

यूनिटेक रिलाएबल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

कोई नहीं

**कोरम:**

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कथपालिया

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

न्याय. राजीव शकधर, (मौखिक)

सि.वि. सं. 26497/2023

1. सभी अपवादों के अधीन अनुमति है

## **सि.वि. सं. 26498-99/2023**

2. उपरोक्त आवेदन अपीलार्थी/राजस्व की ओर से दायर किए गए हैं, जिसमें अपील दायर करने और फिर से दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगी गई है।
  - 2.1 अपीलकर्ता/राजस्व के अनुसार, अपील दायर करने में 24 दिन की देरी और फिर से अपील दायर करने में 28 दिनों की देरी हुई है।
3. अपीलकर्ता/राजस्व की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री पुनीत राय कहते हैं कि दाखिल करने और फिर से दाखिल करने में देरी की अवधि कम है।
4. तदनुसार, उपरोक्त कैप्शन वाले आवेदनों में देरी को माफ किया जाता है।
5. उपरोक्त शीर्षक वाले आवेदनों का निपटान पूर्वोक्त शर्तों में किया जाता है।

## **आयकर अपील 291/2023**

6. यह अपील निर्धारण वर्ष (ए वार्ड) 2012-13 से संबंधित है।
7. अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [संक्षेप में, "ट्रिब्यूनल"] द्वारा पारित दिनांक 29.09.2022 के आदेश को चुनौती देना चाहती है।
8. रिकॉर्ड से उभरने वाले तथ्य, जो अपील पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं।
9. 28.09.2012 को, प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने अपनी आय की विवरणी दायर की, जिसमें उसने 12,83,96,466/- रुपये की हानि घोषित की थी।

- 9.1 निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्षों के दावे की तुलना में प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा रियल एस्टेट परियोजना व्यय के लिए दावा किए गए खर्चों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, प्रत्यर्थी/निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
- 9.2 ऐसा प्रतीत होता है, कि जवाब में, प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने एक उत्तर दायर किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया कि पहले के वर्षों में प्रतिशत पूर्णता पद्धति का पालन किया जा रहा था, जिससे राजस्व सुनिश्चित करने के लिए व्यय अपेक्षित अनुमानों पर आधारित था, और चूंकि परियोजना दिए गए निर्धारण वर्ष में पूरी हो गई थी, इसलिए व्यय में वृद्धि हुई थी।
10. ऐसा प्रतीत होता है, कि एओ ने इस तथ्य को भी चिह्नित किया, कि परियोजना के पूरा होने में व्यय, जिसे प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा 78,40,58,041/- रुपये की राशि के रूप में दावा किया गया था, में एक घटक शामिल था, जो नि.अ. के अनुसार अभी तक खर्च नहीं किया गया था। यह घटक 35,34,96,000/- रुपये के बराबर राशि थी। यह भी प्रतीत होता है, कि हालांकि एक स्पष्टीकरण मांगा गया था, प्रतिवादी/निर्धारिती ने अंततः अपने रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए नुकसान को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नि.अ. ने प्रारंभिक रिटर्न में नुकसान की अनुमति नहीं दी।
11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रारंभिक रिटर्न दाखिल करके दावा किया गया नुकसान 12,83,96,466/- रुपये था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने व्यापार देय राशियों के लिए दर्शाई गई कुल 3,89,61,695/- रुपये की राशि में से 3,02,436/- रुपये भी जोड़े।

- 11.1 इसके लिए नि.अ. द्वारा दिया गया कारण यह था कि भले ही दो संस्थाओं के व्यापार देय को तीन साल से अधिक समय के लिए उत्कृष्ट रूप में दिखाया गया था, कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 [संक्षेप में, "अधिनियम"] की धारा 41 (1) के प्रावधानों का आश्रय लिया और 3,02,436/- रुपये जोड़े, जो उक्त संस्थाओं द्वारा देय थे, इस आधार पर कि वहा देयता की समाप्ति/छूट थी।
12. यह उपरोक्त परिवर्धन के कारण है, अर्थात्, प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा नुकसान का आत्मसमर्पण और व्यापार देय के लिए किए गए जोड़ जो तीन साल से अधिक समय से उत्कृष्ट थे, कि नि.अ. को अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत दंड की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था। शुद्ध परिणाम यह था कि नि.अ. द्वारा जरिये आदेश दिनांक 23.09.2015 के अनुसार 4,36,41,961/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।
13. प्रत्यर्थी/निर्धारिती, असंतुष्ट होने के कारण, आयकर आयुक्त (अपीलें) [संक्षेप में, सीआईटी (ए)] को अपील करने को प्राथमिकता दी। हालांकि, सीआईटी (ए) ने अपील को खारिज कर दिया, और नि.अ. द्वारा पारित दंड आदेश को बरकरार रखा। यह इस पृष्ठभूमि में है, कि प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने अधिकरण के साथ दूसरी अपील को प्राथमिकता दी।
14. अधिकरण ने ऊपर दी गई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटारा किया और जहां तक दंड की कार्यवाही का संबंध था, उसके द्वारा देखे गए दोष के आधार पर दंड आदेश को रद्द कर दिया।

15. अधिकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के साथ पठित धारा 274 के तहत जारी किए गए 14.03.2015 के नोटिस में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि किस अंग के तहत जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्था/निर्धारिती को जो नोटिस दिया गया था, उसमें यह इंगित नहीं किया गया था कि क्या आय छिपाने के कारण जुर्माना लगाया जा रहा था, या इस कारण से कि उसने गलत विवरण प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर अधिकरण, **सीआईटी बनाम एसएसए का एमराल्ड मीडोज** (2016) 73 taxmann.com 248 (एससी) ने कहा कि दंड की कार्यवाही को रद्द करना होगा।
16. सुविधा के लिए, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार निकाला गया है:

*"7.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेसर्स एसएसए एमराल्ड मीडोज, (2016) 73 taxmann.com 248 (एससी) के मामले में माननीय कर्णाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध राजस्व द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जिसके द्वारा निर्धारिती के पक्ष में समान मुद्दे का निर्णय लिया गया था। माननीय कर्णाटक उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मेसर्स एसएसए के एमराल्ड मीडोज (सुप्रा) के मामले में निर्णय का ऑपरेटिव हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -*

*"2. यह अपील कानून के निम्नलिखित सारभूत विधि प्रश्नों को उठाते हुए दायर की गई है:*

*(1) क्या चूक यदि निर्धारण अधिकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए दंड की कार्यवाही शुरू की जा रही है या आय छिपाने के लिए जुर्माना आदेश रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही यह उचित संदेह से परे साबित हो गया हो कि निर्धारिती ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आय छिपाई थी?*

(2) क्या, तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, अधिकरण को कानून में उचित ठहराया गया था कि धारा 274 आरडब्ल्यूएस 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना नोटिस कानून में खराब है और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ धारा 271 (1 बी) के संशोधन के बावजूद अमान्य है और संशोधन के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने इसके लिए संतुष्टि को ठीक से दर्ज करके जुर्माना शुरू किया है?

(3) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल को जारी किए गए नोटिस के आधार पर राजस्व के खिलाफ अपील का फैसला करने में न्यायसंगत था, धारा 274 के तहत मूल्यांकन आदेश को ध्यान में रखे बिना जब निर्धारण अधिकारी ने निर्दिष्ट किया है कि निर्धारिती ने आय का विवरण छुपाया है?

3. अधिकरण ने निर्धारिती होल्डिंग द्वारा दायर अपील की अनुमति दी है आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 271(1)(सी) के साथ पठित धारा 274 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी किया गया नोटिस कानून की नजर में खराब है। चूंकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के किस अंग के तहत दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी चाहे आय का विवरण छुपाने के लिए हो या आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए हो। अधिकरण, निर्धारिती की अपील की अनुमति देते हुए, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय पर भरोसा किया है जो आयुक्त या आयकर बनाम मंजूनाथ कपास और जिनिंग फैक्ट्री (2013) 359 आईटीआर 565 के मामले में प्रदान किया गया है।

4. हमारे विचार में, चूंकि मामला इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले से आच्छादित है, इसलिए हमारी राय है, इस अपील में न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए सारभूत विधि प्रश्न नहीं उठता है, अपील तदनुसार खारिज किया जाता है।

[जोर हमारा है]

17. उपर्युक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने वास्तव में उक्त मामले में कर्णाटक उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की थी, जिसने बदले में अपने स्वयं के

न्यायालय में **मंजुनाथ कॉटन & जिनिंग फैक्टरी**, (2013) 359 आईटीआर 565 के निर्णय पर भरोसा किया था।

18. इसके अलावा, अधिकरण ने **पीसीआईटी बनाम सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (2021)432 आईटीआर 84 (डेल) के वाद में न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय को भी नोट किया।
19. हम नोट कर सकते हैं कि यहां तक कि 14.03.2015 के मूल्यांकन आदेश, जिसके तहत दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी, ने यह नहीं बताया कि याचिकाकर्ता के लिए धारा 271(1)(सी) के किस अंग को लागू किया जा रहा था। यह नि.अ. द्वारा किए गए निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट है:  

*"अधिनियम कि धारा 271 (1) (सी) के तहत आय छिपाने और आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अलग से दंड कार्यवाही शुरू की जा रही है।"*
20. हम नोट कर सकते हैं कि इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ, जिसमें से हम में से एक [यानी, राजीव शकधर, जे.] एक पक्षकार थे, **पीसीआईटी बनाम मीनू बखशी** (7) टीएमआई 1370-दिल्ली के वाद में उसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।
21. दंड की कार्यवाही निर्धारिती के लिए सिविल परिणामों को लागू करती है। नि.अ को भौतिक विवरणों पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है, और स्पष्ट रूप से इंगित करें कि दंड की कार्यवाही को ट्रिगर करते समय प्रतिवादी/निर्धारिती के खिलाफ क्या रखा जा रहा है।
22. यदि नि.अ यह निष्कर्ष निकालता है कि अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत कोई मामला बनता है, तो उसे स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा कि उक्त प्रावधान का कौन सा अंग आकर्षित है। हमारे ऐसा कहने का कारण यह है

कि किसी और चीज के अलावा, प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा किए गए उल्लंघन के आधार पर आर्थिक बोझ अलग-अलग हो सकता है। किसी दिए गए मामले में, जहां छिपाव हुआ है, एक भारी बोझ लगाया जा सकता है, ऐसी स्थिति की तुलना में जहां एक निर्धारिती गलत विवरण प्रस्तुत करने में शामिल है।

23. इसलिए, निर्धारण अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह मोटे तौर पर उस प्रावधान/अंग के बारे में इंगित करे जिसके तहत निर्धारिती के खिलाफ दंड की कार्यवाही शुरू की जाती है।
24. स्पष्ट है, इस तत्काल मामले में ऐसा नहीं हुआ है।
25. वस्तुतः, यहां तक कि मूल्यांकन आदेश में, जिसके तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के किस अंग को उत्प्रेरित किया गया था।
26. इस प्रकार, दी गई परिस्थितियों में, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हमारे अनुसार, यह मुद्दा अच्छी तरह से सुलझा हुआ है, और इसलिए, इस अपील पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विचार के लिए सारभूत विधि प्रश्न नहीं उठता।
27. तदनुसार, अपील बंद की जाती है।
28. रजिस्ट्री आज दिए गए फैसले की एक प्रति प्रतिवादी/निर्धारिती को पक्षकारों के ज्ञापन में दिए गए पते पर भेजेगी, और यदि संभव हो तो ई-मेल के माध्यम से भी भेजेगी।
29. पक्षकार आदेश की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के आधार पर कार्य करेंगी।



(राजीव शकधर)  
न्यायाधीश

(गिरीश कठपालिया)  
न्यायाधीश

19 मई 2023  
वि

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।